मैं पानी का भुगतान क्यों करूं?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए समुदाय आधारित वित्त पोषण)

ग्रामीण आधारभूत संरचना केंद्र

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)

राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030

www.nirdpr.org.in

अप्रैल 2022

प्रस्तावना

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (जेजेएम) दिशानिर्देश, ग्राम पंचायतों (जीपी) को ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए निर्दिष्ट करते है।उनमें से सबसे आवश्यक हैं: सिस्टम का तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन। अक्सर जब ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जल उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के बारे में चर्चा शुरू करते हैं, तो समुदाय कई प्रश्न पूछता है। उनके प्रश्न आमतौर पर रूढ़ियों पर आधारित होते हैं जैसे: 'पानी जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। क्या यह एक निर्वाचित स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत) की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इसे मुफ्त में उपलब्ध कराए? 'मैं पानी के लिए क्यों भुगतान करूं'? यह बार-बार दोहराया जाने वाला प्रश्न है जो ग्रामीण परिवारों द्वारा विस्तार कार्यकर्ता से पूछा जाता है।

उनका तर्क है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित पानी और स्वच्छता, राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित ग्राम पंचायत का आवश्यक कार्य हैं। यह पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वे इस तरह की सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए निधि का प्रबंध करें ।। मुख्य रूप से उनका एक ही सवाल है। लेकिन वे इसे कई अलग-अलग शब्दों में निरंतर प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पूछते हैं - कुछ तार्किक और अन्य वाद-विवाद के जैसे ।

इस प्रकार, जल उपयोगकर्ताओं से जल शुल्क संग्रह के संबंध में अनुभव हमेशा एक चुनौती रहा है। समुदाय स्तर के प्रशिक्षकों को एक स्पष्ट व्याख्या देने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त कार्य करना पड़ता है। एक प्रशिक्षक की प्रतिक्रिया तत्काल या सतही नहीं हो सकती। समुदाय के सदस्यों के अपने कारण हैं, वे क्यों सोचते हैं कि जीपी या राज्य को भुगतान करना चाहिए। एक प्रशिक्षक के रूप में उनकी सोच को फिर से स्थापित करने के लिए आपका स्पष्ट मत क्या है? क्या आप तैयार है? क्या आप आश्वस्त कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को आश्वस्त कर पा रहे हैं?

आपके तार्किक और तकनीकी कारण क्या हैं जो आपको लगता है कि समुदाय को भुगतान करना चाहिए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जेजेएम के दिशानिर्देश ऐसा कहते हैं, या आप आश्वस्त हैं कि समुदाय को भुगतान करना चाहिए ताकि लाभ बना रह सके? मुद्दा यह है कि समुदाय के सदस्यों के पास एक हजार कारण हैं कि वे क्यों सोचते हैं कि उन्हें पीने के पानी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक स्तर पर एक प्रशिक्षक के रूप में, लोगों को यह समझाने और विश्वास दिलाने के लिए आपका तर्क क्या है कि उन्हें पानी के लिए भुगतान करना चाहिए - और यह उनके हित में है? वैसे, यह प्रतिवाद विकसित करने के बारे में नहीं है। न ही यह अकादमिक स्क्रैप में जा रहा है। विचार यह है कि इसे एक व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए।

इस प्रश्नोत्तरी का उपयोग प्रशिक्षण सत्र में भूमिका निभाने के लिए किया जाना है, जहां एक प्रतिभागी सामुदायिक स्तर के प्रशिक्षक की भूमिका निभा सकता है, और एक या कुछ अन्य एक प्रतिरोधी समुदाय की भूमिका निभा सकते हैं। प्रशिक्षक का कार्य प्रतिरोधी समुदाय को पानी का भुगतान करने के लिए समझाना और विश्वास दिलाना है।

प्रश्नकर्ता- 1: मैं पानी का भुगतान क्यों करूं?

प्रशिक्षक: सरकार ने जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण में निवेश किया है। यह एकमुश्त निवेश है, सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वहन करती है। प्रत्येक घर में पानी की दैनिक आपूर्ति पर होने वाले आवर्ती खर्च को उपयोगकर्ता समुदाय द्वारा वहन किया जाना है।

प्रश्नकर्ता-2: दरअसल, हर घर को कार्यात्मक हाउस टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण या मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है। मैं इसे समझ सकता हूँ। लेकिन, केवल सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए, क्या हमें धन की आवश्यकता है?

प्रशिक्षक: क्या आप अपने घर का मासिक बिजली बिल भर रहे हैं?

प्रश्नकर्ता - 3: हाँ। मैं करता हूँ। लेकिन मेरे घरेलू स्तर के बिजली बिल का पानी की आपूर्ति जैसी सामान्य सुविधा से क्या लेना-देना है?

प्रशिक्षक: मैं बस यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आपने अपने घर में बिजली कनेक्शन लेने के लिए एक बार निवेश किया है, और उसके बाद कभी भी अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। आप अपने मासिक बिजली बिल का भुगतान समय पर करते हैं, है ना? इस प्रकार, यह एक निजी सुविधा या सामान्य सुविधा हो - उपयोगकर्ताओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है जिसका आनंद वे लेते हैं, वे उस सुविधा के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों का भुगतान करते हैं। मुझे आशा है कि आप इससे सहमत होंगे। 'सेवा भुगतान के उपयोगकर्ता' ताकि कोई भी सेवा प्रदाता लाभों को बनाए रखने में मदद कर सके।

प्रश्नकर्ता- 4: निजी सुविधा के लिए, हाँ। लेकिन, एक सार्वजनिक सुविधा के लिए, मुझे भुगतान क्यों करना चाहिए? यही मेरा मूल प्रश्न है। यदि यह एक सार्वजनिक सुविधा है तो इसे वास्तव में ग्राम पंचायत को ही वहन करना पड़ता है, है न?

प्रशिक्षक: मैंने पहले उल्लेख किया था कि सरकार ने तकनीकी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा करने में सक्षम होने के लिए, सरकार को पैसा कहां से मिला? मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि आपको जलापूर्ति का बुनियादी ढांचा, सड़क, स्ट्रीट लाइट आदि उपलब्ध कराने के लिए सरकार के राजस्व का क्या स्रोत है?

प्रश्नकर्ता-5: सरकार लोगों से तरह-तरह के कर वसूल करती है। यह आयकर, संपत्ति कर, जीएसटी आदि हो सकता है। इसलिए सरकार के पास पैसा है।

प्रशिक्षक: हां, केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न कर लगाती हैं, जो सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत हैं। कर के पैसे का उपयोग सड़क, स्ट्रीट लाइट, गरीबों के लिए घर बनाने, जलापूर्ति जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए

किया जाता है। ये एकमुश्त खर्च के रूप में व्यय किया जाता हैं। उदाहरण के लिए, पीएमएवाई-जी कार्यक्रम के तहत एक गरीब परिवार को एक घर की मंजूरी दी जाती है। यह एकमुश्त खर्च है जो सरकार उस परिवार को प्रदान करती है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार प्रत्येक संक्रांति त्यौहार से पहले सभी पीएमएवाई-जी घरों की मरम्मत और पुताई करेगी, है ना? यही मामले की जड़ है। घर के उपयोगकर्ताओं को रखरखाव और मरम्मत करना है, है ना? पेयजल आपूर्ति के मामले में भी यही स्थिति है।

प्रश्नकर्ता -6 : एक बार मकान मिल जाने के बाद मकान मालिक को रख-रखाव का ध्यान रखना पड़ता है। यह तार्किक है। पर मेरा सवाल पानी के भुगतान के बारे में है, जो एकमुश्त निवेश से बनाए गए स्रोतों से मुफ्त रूप से उपलब्ध है।

प्रशिक्षक: फिर से, हम उसी वर्ग में वापस आ गए हैं! स्रोत और सुविधाएं सरकार द्वारा किए गए एकमुश्त निवेश से सृजित की गई थीं। लेकिन, हमारे गांवों में एक जल आपूर्ति ऑपरेटर है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर घर को नियत समय पर सुरक्षित जल मिले; आपूर्ति किए गए जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे जल को क्लोरीनेट करना होगा; उसे पंप संचालित करना होता है, जिसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है; पंचायत को बिजली बिलों का भुगतान बिजली बोर्ड को करना होता है। यदि बिजली बोर्ड के बिल का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो बिजली बोर्ड बिजली की आपूर्ति में कटौती कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत पानी प्रदान करने में असमर्थ होगा।

एक और उदाहरण लेते हैं, सरकार हमारे गांवों को स्ट्रीट लाइट प्रदान करती है। स्ट्रीट लाइट एकमुश्त निवेश हैं। जब एक स्ट्रीट लाइट फ्यूज हो जाती है, तो उसे बदलने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हर बार ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाने पर सरकार बदलने नहीं आती है। यह स्थानीय सरकार है जिसे इसे बनाए रखना है, है ना? यहां एक संबंधित मुद्दा यह है कि हर महीने बिजली बिल का भुगतान कौन कर रहा है ताकि बिजली बोर्ड स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति में कटौती न करे? यह ग्राम पंचायत है, है ना? इसका मतलब है कि अगर कुछ लाभों को बनाए रखना है तो इसमें कई आवर्ती खर्च शामिल हैं। इसलिए, जीपी के लिए बिजली बिल का भुगतान करने और स्ट्रीट लाइट, या पानी की आपूर्ति सुविधाओं को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए यह काफी तार्किक है कि उपयोगकर्ताओं को भुगतान करना होगा।

प्रश्नकर्ता – 7: यदि उपयोगकर्ता भुगतान नहीं करते हैं या सेवा के लिए भुगतान करना बंद कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई ग्राम पंचायत पेयजल उपलब्ध कराना बंद कर सकती है? मुझे लगता है, व्यावहारिक रूप से इसे रोकना असंभव है।

प्रशिक्षक: व्यावहारिक रूप से यह तुरंत नहीं रुकता, लेकिन जल्दी ही रुक जाता है। चूंकि पंचायत कार्यकर्ता मूल रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, वे समुदाय के सदस्यों की नाराजगी झेलना नहीं चाहेंगे। इसलिए, वे बिजली बोर्ड से बिजली आपूर्ति में कटौती न करने का अनुरोध करके इसे चलाने का प्रयास करेंगे; और वाटरमैन को आश्वस्त करना कि जीपी में कुछ धनराशि प्राप्त होते ही उन्हें उनका वेतन मिल जाएगा; सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध करके कि जीपी को सरकार से कुछ निधि प्राप्त होने के बाद उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। यह अल्पावधि के लिए सिस्टम को चलाने में मदद कर सकता है। लेकिन, यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। यदि बिजली बोर्ड का बकाया लंबे समय तक नहीं चुकाया जाता है,

तो जाहिर है, बढ़ते अतिदेय पर उनके उच्च अधिकारियों का दबाव होगा। बिजली आपूर्ति में कटौती कर स्थानीय बिजली बोर्ड विभाग को कार्रवाई करनी है। अधिक समय से लंबित वेतन के विरोध में कुछ समय बाद जलकर्मी काम करना बंद कर देंगे। पाइपलाइनों में मरम्मत और रिसाव के लिए जीपी के पास कोई निधि नहीं होगी। जब बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है, तो वितरण के लिए पानी की टंकी में पानी नहीं भरा जा सकता है। अंतत: जल सेवा वितरण को रोकना पड़ता है। ऐसे में हमारे पास पाइपलाइन होगी। नलों में पानी नहीं आएगा।

प्रश्नकर्ता– 8: यदि उपयोगकर्ताओं को ऐसी सभी सेवाओं के लिए भुगतान करना है, तो पंचायत क्यों मौजूद है? पंचायत का क्या उपयोग है? हम सभी ने वोट क्यों दिया और एक स्थानीय निकाय का चुनाव क्यों किया, अगर वे हमें भुगतान करने के लिए कहेंगे?

प्रशिक्षक: उपयोगकर्ता किसी भी गांव में मतदाताओं से अलग नहीं हैं। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। दूसरे शब्दों में, सभी ग्रामीण परिवार विभिन्न सेवाओं के 'उपयोगकर्ता' हैं। उपयोगकर्ताओं के रूप में यह काफी तार्किक है कि उन्हें इन सुविधाओं को एक साथ बनाए रखना चाहिए। उनकी ओर से उन्होंने एक स्थानीय निकाय बनाया, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत इन सेवाओं का प्रबंधन और रखरखाव करती है। अब, जब तक उपयोगकर्ता भुगतान नहीं करेंगे, ग्राम पंचायतों को इन सुविधाओं के संचालन या रखरखाव के लिए निधि कहाँ से मिलेगी? यह कहने जैसा है: मैं प्रतिदिन एक गाय का दूध दुहूंगा, लेकिन मैं गाय को न खिलाऊंगा और न ही उसे पानी पिलाऊंगा।

प्रश्नकर्ता- 9: क्या ग्राम पंचायतों को इन सुविधाओं को बनाए रखने/इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है?

प्रशिक्षक: आपने सही सवाल पूछा है। जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान लेकर आई है। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत सालाना निधि प्राप्त हो रही है। इसे पंचायतों को 15वां वित्त आयोग अनुदान के रूप में जाना जाता है। वास्तव में, 15वें वित्त आयोग की निधि की शर्तों के अनुसार, साठ प्रतिशत का उपयोग पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों के लिए किया जा सकता है; और शेष 40 प्रतिशत का उपयोग ग्राम सभा द्वारा निर्धारित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण स्थानीय निकाय पानी, स्वच्छता, और स्वास्थ्य (वॉश) पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण नागरिकों को बुनियादी सेवाएं देने के लिए उस निधि का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार, ग्राम पंचायत स्तर पर पानी और स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखने के लिए यह निधि उपलब्ध है।

आपको यह भी समझना होगा कि 15वां वित्त आयोग निधि तो केक का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे कई टुकड़ों में काटना पड़ता है। इस निधि का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाना है जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित पानी और स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव; अपशिष्ट संग्रह वाहनों की मरम्मत और रखरखाव, सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई आदि। इसलिए, 15वां वित्त आयोग निधि एक महत्वपूर्ण आकस्मिक निधि की तरह काम कर सकता है, जब एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क अपर्याप्त

होते हैं। हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि पानी की आपूर्ति पर पूरे संचालन और रखरखाव खर्च को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त हो सकती है।

प्रश्नकर्ता– 10: यदि ग्राम पंचायत 15वें वित्त आयोग की निधि के कुछ हिस्से का उपयोग संचालन और रखरखाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकती है, तो हर परिवार को भुगतान क्यों करना चाहिए? यह पर्याप्त होगा यदि कुछ परिवार, जो भुगतान कर सकते हैं, भुगतान करें। बाकी जीपी प्रबंधन कर सकता है, है ना?

प्रशिक्षक: आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, और यह आपको बिल्कुल तर्कसंगत लगता है! अगर यह आपको तर्कसंगत लगता है, तो यह बाकी सभी के लिए पर्याप्त तर्कसंगत है, है ना? यह सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट की तरह है। स्ट्रीट लाइट के लिए कौन भुगतान करना चाहता है? यदि कुछ भुगतान कर रहे हैं और अन्य भुगतान नहीं करते हैं, तो अंततः भुगतान करने वाले भी भुगतान करना बंद कर देंगे। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक घर (और संस्थानों और रेस्तरां आदि सहित जल सेवा के सभी उपयोगकर्ता) उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करें। उपयोगकर्ता शुल्क की राशि ग्राम सभा द्वारा परिवारों के सामर्थ्य और पानी की आपूर्ति में शामिल खर्चों पर विचार करते हुए तय की जा सकती है।

इसे देखने का तर्कसंगत तरीका यह है कि एक मोटा बजट तैयार करें कि आपकी ग्राम पंचायत हर महीने पानी की आपूर्ति से संबंधित खर्चों जैसे बिजली बोर्ड के बिल, मरम्मत और रखरखाव, पंप ऑपरेटरों के वेतन आदि पर कितना खर्च कर रही है। इसी तरह, गणना करें कि उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से कितना राजस्व उत्पन्न होता है। हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या यह अधिशेष या घाटा दिखाता है। सभी जल उपयोगकर्ताओं से संग्रह करने के बाद, घाटा, यदि कोई हो, को 15वें वित्त आयोग की निधि से निकाला जा सकता है। गैप पूर्ति निधि का यही मतलब है। इस प्रकार ग्राम पंचायत 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग न केवल जलापूर्ति के लिए बल्कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के रखरखाव, जल निकासी की सफाई आदि से संबंधित खर्चों के लिए भी कर सकेगी।

प्रश्नकर्ता-11: क्या नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लोग पानी के लिए भुगतान कर रहे हैं?

प्रशिक्षक: हाँ। वे पानी के लिए भुगतान करते हैं। ज्यादातर इसे सालाना आधार पर एकत्र किया जाता है।

प्रश्नकर्ता– 12 : हो सकता है, वे भुगतान कर सकें। लेकिन, गरीब ग्रामीण लोग भुगतान कैसे कर सकते हैं?

प्रशिक्षक: यह सच है - ग्रामीण क्षेत्रों में - ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं। यदि ग्राम सभा निर्णय लेती है तो कुछ गरीब परिवारों को स्थानीय रूप से विकसित मानदंडों के आधार पर 'अत्यधिक गरीब' के रूप में पहचाना जा सकता है। फिर भी, यह संख्या कुल परिवारों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसे परिवारों को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जा सकती है। यह पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका संज्ञान लेते हुए, ग्राम पंचायत घरों, संस्थानों, रेस्तरां, चाय की दुकानों और मैरिज हॉल आदि के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता शुल्क / टैरिफ तय कर सकती है। यदि कुछ गरीब परिवारों को आधिकारिक रूप से भुगतान से छूट दी जाती है तो ऐसी टैरिफ व्यवस्था उो संतुलित करेगी।

प्रश्नकर्ता- 13: पहले कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं देता था। इसके बावजूद, ग्राम पंचायतें 'किसी तरह' यार्ड के नलों और सामान्य जल संग्रह स्थानों में पीने के पानी की आपूर्ति का प्रबंध कर रही हैं। यह कैसे संभव हुआ? अगर पहले ऐसा संभव था तो अब क्यों नहीं?

प्रशिक्षक: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप जो कहते हैं वह काफी हद तक सच होता है। मैं सराहना करता हूं कि आपने कहा: 'जीपी "किसी तरह" प्रबंधन कर रही हैं। लेकिन आपको"किसी तरह यह समझना होगा कि " इसके पीछे क्या है । और हम अभी या भविष्य में उसी रास्ते पर चलने का जोखिम क्यों नहीं उठा सकते।

अतीत में मुझे यकीन है कि आपने अक्सर शिकायत की है कि ग्राम सभा की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, लेकिन उनमें से शायद ही कुछ को लागू किया गया था, है ना? इसका कारण यह नहीं है कि पंचायतों को उनमें से अधिकांश को लागू करने के लिए धन नहीं मिला। लेकिन अक्सर बिजली बोर्ड को भुगतान किए जाने वाले बकाया; जलकर्मियों को भुगतान की जाने वाली वेतन देय राशि; लीकेज पाइप, नल आदि की मरम्मत के लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाले कुछ सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए जाने वाले लंबित बिल जैसे रखरखाव देय राशि के भुगतान के लिए जीपी द्वारा निधियों का उपयोग करना पड़ता था। आप किसी भी समय अपने जीपी की जांच कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि बिजली बोर्ड पर जीपी के बकाया बिलों की राशि बहुत बड़ी है। जब भी बिजली बोर्ड को बिजली काटने की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो बीडीओ या जिला पंचायत के अध्यक्ष / सहायक निदेशक या जिला मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप करते हैं और बिजली बोर्ड को बकाया राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, जब जीपी को निधि की अगली किस्त जारी की जाती है।

तदनुसार, उदाहरण के लिए, जब 15वें वित्त आयोग की निधि कुछ विकास उद्देश्यों के लिए जारी की जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास बिजली बोर्ड को देय राशि को तुरंत चुकाने के लिए जीपी को निर्देश देने का अधिकार होता है। इसी तरह महीनों से नहीं मिला बकाया वेतन दिलाने की गुहार लगाने वाले जलसेवकों की ओर से लगातार दबाव बना हुआ है। इस प्रकार, ग्राम पंचायतों में यह एक सामान्य प्रथा है कि विकास उद्देश्यों के लिए निधि को लंबित बिजली बिलों को चुकाने या स्वच्छता कर्मचारियों आदि सहित पंचायत श्रमिकों के वेतन बकाया का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। दुर्भाग्य से, यह गांव के आम निवासियों के संज्ञान में नहीं आता है। वे पारित प्रस्तावों को लागू नहीं करने के लिए जीपी को दोषी ठहराते हैं।

इस प्रकार, यह कभी-कभी बिजली बोर्ड का बिल होता है; कभी-कभी यह ऑपरेटरों का वेतन लंबित होता है; और अन्य समय में, यह कुछ विक्रेताओं की बकाया राशि है जो मोटर की मरम्मत के लिए सामग्री की आपूर्ति करते हैं या पानी की आपूर्ति में सही ब्रेक डाउन सेट करते हैं। इन सब में जो होता है वह एक ही होता है - विकास उद्देश्यों के लिए दिया गया पैसा बकाया भुगतान के लिए दिया जाता है, जो अन्यथा उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के माध्यम से भुगतान किया जाता। जैसा पहले होता था।

यही हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क से बिजली बोर्ड की बकाया राशि, वाटरमैन वेतन आदि का भुगतान कर सकते हैं, तो विकास उद्देश्यों के लिए धन जैसे कि 15 वें वित्त आयोग निधि का ग्राम सभा की प्राथमिकता के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया जा सकता है और खर्च किया जा सकता है। यदि हम ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय स्वशासन प्रणाली चला रहे हैं तो क्या हमें इस ओर नहीं बढ़ना है?

यह एक लंबा जवाब है। लेकिन, आपको यह जानने की जरूरत है, ताकि आप तय कर सकें कि आपको क्या लगता है कि भविष्य कैसा होना चाहिए।

प्रश्नकर्ता – 14: मैं समझता हूँ, लेकिन जलापूर्ति के अलावा ठोस कचरा प्रबंधन आदि जैसी अन्य सेवाएँ भी हैं। क्या इसके लिए हमें फिर से अलग से भुगतान करना होगा?

प्रशिक्षक: ग्राम पंचायत में राजस्व उत्पन्न करने के कई तरीके हैं। आम तौर पर ग्राम पंचायतें गृह-कर की मांग करती हैं और अधिकांश पंचायतों को लगता है कि यह स्थानीय कर राजस्व का एकमात्र स्रोत है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय कर राजस्व उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों को समझाने की कोशिश करना यहाँ एक विषय से अलग हटना होगा। इसलिए, मैं यहां उनकी चर्चा को टालता हूं। पानी और स्वच्छता संबंधी खर्चों को बनाए रखने के उद्देश्य से, ग्राम पंचायतें जल उपयोगकर्ता शुल्क जमा कर सकती हैं। लेकिन फिर से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी की सफाई आदि में भी खर्च शामिल हैं। इसलिए, क्या सुझाव दिया जा सकता है कि जीपी 'उपयोगिता शुल्क' एकत्र करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें सभी पानी और स्वच्छता, पानी से संबंधित खर्च, अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल होना चाहिए।

इसे मासिक या त्रैमासिक बनाने के बजाय सालाना एकत्र किया जा सकता है। लोगों को मुश्किल महसूस न हो इसके लिए वार्षिक गृह कर की मांग के साथ जल कर (या 'उपयोगिता कर', जो पानी और गांव की सफाई से संबंधित है) को एकत्र किया जा सकता है। इसे हर साल दिसंबर में वसूल करना बेहतर हो सकता है और लोगों से अगले वर्ष के 31 मार्च तक भुगतान करने के लिए कहा जाता है। भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए (i) जनवरी (अगले वर्ष) में भुगतान करने वालों को 10% की छूट दी जा सकती है; (ii) फरवरी में भुगतान करने वालों को 5% की छूट दी जा सकती है; और (iii) मार्च में भुगतान करने वालों को पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

इसी तरह, 31 मार्च के बाद भुगतान करने वालों को महीने के अनुसार 5% या 10% का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे जीपी हैं जहां लोग संपत्ति कर या गृह कर सहित - किसी भी कर का भुगतान करने की जहमत नहीं उठाते। ऐसे स्थानों में, जब कोई परिवार सरकारी योजनाओं के तहत कुछ प्रमाण पत्र या लाभ प्राप्त करने के लिए जीपी कार्यालय का दौरा करता है, तो जीपी ऐसे लंबित करों को वसूल करने की कोशिश करते हैं। ग्राम पंचायत उस अवसर का उपयोग ऐसे परिवारों से कर (वार्षिक जल कर सहित) वसूल करने के लिए करती है। परिवारों को गृह कर / संपत्ति कर / उपयोगिता कर की रसीदें संलग्न करने के लिए कहा जाता है ताकि जीपी से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। यह कर वसूल करने का एक प्रकार का

जबरदस्ती का तरीका है, तब जब लोगों में जीपी को करों का भुगतान करने को हल्के में लेने की प्रवृत्ति होती है।

सब कह कर दिया और कर दिया । मासिक संग्रह के बजाय वार्षिक संग्रह को सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। मासिक कर संग्रह के लिए जाना श्रमसाध्य और थकाऊ है। फिर से, हर घर के लिए इसका लेखा-जोखा - हर महीने चूककर्ताओं की सूची तैयार करना आदि पहले से ही कर्मचारियों की कमी वाले ग्राम पंचायतों में अनावश्यक लिपिक कार्य हैं। इसे सालाना बेहतर किया जा सकता है।

निष्कर्ष

केंद्र या राज्य सरकार की तरह, यह काफी व्यवस्थित और क्रमबद्ध है कि अगर सभी सुविधाओं को स्थायी लाभ प्रदान करना है तो स्थानीय सरकारों को पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए अपने स्रोत से राजस्व उत्पन्न करना होगा। यह स्थानीय शासन का एक मूल सिद्धांत है।

डॉ आर रमेश

एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर

rramesh.nird@gov.in
rramesh.nirdpr@gmail.com